

प्रेषक,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०
भागीदारी भवन, गोमती नगर,
लखनऊ ।

सेवा में

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
समाज कल्याण अनुभाग-३

पत्रांक:- ५३१ /१-७/९२-९३ /श०प्र०स० लखनऊ, दिनांक: २० अगस्त, २००८

विषय:- विमुक्त जातियों की सूची से त्रुटिवश विलुप्त हुई जातियों को पुनः शामिल किये जाने सम्बन्धित गुजर सद्भावना सभा मुजफ्फर नगर के प्रार्थना पत्र का अग्रसारण ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सूरत सिंह वर्मा, जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, मुजफ्फर नगर के पत्र दिनांक: ७-८-२००८ एवं सद्भावना सभा, मुजफ्फर नगर के पत्र (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो विमुक्त जातियों के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं०-५२९ /२६-३-२००१- ३(२)/८० दिनांक: २७ फरवरी, २००१ में शासनादेश वर्ष १९६१ एवं वर्ष १९९२ का ही सन्दर्भ लिये जाने एवं शासनादेश वर्ष १९६२ एवं १९९४ को सन्दर्भ में न लिये जाने की विधियां १९ जातियों जो छूट गई हैं को पुनः विमुक्त जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने के सामन्थ में हैं।

अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-८९९(ए) /२६-७००(५) /१९५९ दिनांक: १२ अ३. १९६१ में उ०प्र० की विमुक्त जातियों की सूची प्रकाशित की गई इसमें ११ रथायी निवास करने वाली २५ घुमन्तृ जातियों की सूची जारी की गई। इस शासनादेश में यह अंकित किया गया था कि अनुसूचित जाति में अंकित जातियों को इसी सूची से अलग कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न)। इस शासनादेश को शासनादेश दिनांक: १२-१-६२ द्वारा खंडित करते हुए ३० विमुक्त जातियों की सूची संलग्न की गई। इसी क्रम ने यह भी (छाया प्रति संलग्न) में ३० जातियों के नाम सम्मिलित थे। (छाया प्रति संलग्न) इसी क्रम ने यह करना है कि दिनांक: १२-५-६१ के शासनादेश के क्रम में शासन ने एक नया शासनादेश अवगत कराना है कि दिनांक: १२-५-६१ के शासनादेश में १९ जातियों जो अनुसूचित जाति में आती थी उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गय था। एवं पुनर्विचारोपरान्त इन १९ जातियों को भी विमुक्त जाति की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। इस शासनादेश में भी पुनः एक त्रुटि हुई वह यह कि शासनादेश दिनांक: १२ अ३. १९६१ नवम्बर, १९६१ में पुनः दिनांक: १२-३-२१९६१ में जारी की गई सूची की पुनरावृत्ति की गई, परन्तु क्रमांक-२ पर थी को पुनः वर्ष १९६२ के शासनादेश में भी अंकित कर दिया गया जबकि शासनादेश दिनांक: १२-१-१९६२ में "गीधिया" जाति क्रमांक-१४ पर है जो ३० जातियों में एक है।

विमुक्त जातियों से ही सम्बन्धित शासनादेश सं०-३२७६ /२६-३-९२-३(४२) /९० देनांक: १२ अ३. १९६१ में पुनः दिनांक: १२-३-२१९६१ में जारी की गई सूची की पुनरावृत्ति की गई, परन्तु क्रमांक-१४ पर है जो ३० जातियों में एक है।

S.A.

शासनादेश सं0-1019(1) / 26-3-92-3(42)90 दिनांक: 22 अप्रैल, 1994 द्वारा पुनः छूट गई 19 जातियों को इसमें समिलित कर लिया इसमें भी "भर" जाति दोनों शासनादेशों में अंकित पायी गई जबकि "गीधिया" जाति को इसमें भी समिलित नहीं किया गया।

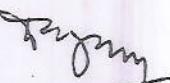
वर्ष 2001 में विमुक्त जातियों से सम्बन्धित नवीन शासनादेश सं0-529 / 26-3-2001-3(2) / 80 दिनांक: 27 फरवरी, 2001 पुनः जारी किया गया जिसमें दिनांक: 12-3-1961 एवं दिनांक: 28-11-1992 में जारी सूची को ही प्रकाशित किया गया है। जबकि पुनः दिनांक: 26.3.1962 व 22.4.1994 के शासनादेशों की अनदेखी की गई है।

इसी विषय के अन्तर्गत शासन के पत्रांक-449सी0एम0 / 26 -3-2007 -3(33) / 2007 दिनांक: 21 सितम्बर, 2007 के अनुपालन में संस्थान के पत्रांक-874 / 1-50 / 2003-04 / शो0प्र0सं0 दिनांक: 2 जनवरी, 2008 द्वारा उत्तर प्रेषित किया गया है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः संस्थान का मत है कि विमुक्त जातियों से सम्बन्धित एक नवीन शासनादेश जारी करने की अत्यन्त आवश्यकता है जिसमें ४० वाई० अयंगर समिति की रिपोर्ट में अंकित "गीधिया" जाति जो कतिपय कारणों से विमुक्त जाति की सूची में छूट गई है सहित छूटी हुई 19 जातियों को 27 फरवरी, 2001 के शासनादेश में अंकित 11 स्थिरवासी जातियों के साथ शामिल करते हुये कुल 30 स्थिरवासी विमुक्त जातियों का नवीन शासनादेश जारी करने का कष्ट करें। घुमन्तू विमुक्त जातियों के रूप में अंकित 25 जातियों यथावत बनी रहें।

सलंनक-उपर्युक्तानुसार

भूतीय,


(दीना नाथ गुप्ता)
संयुक्त निदेशक।

जय भीम
नां० काशीपुर अमर रहे

बाबा साहब अमर रहे।

जय भारत
माननीय बहन कु० मायावती जिन्मामाद ॥

बहुजन समाज पार्टी

जनपद मुजफ्फरनगर

माननीय बहुजन कु० मायावती
अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी
एवं मुख्यमंत्री (उ०प्र०)

केन्द्रीय कार्यालय:-
गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली।

साझथ एवन्यू: लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ
प्रदेश कार्यालय:-



मा० ३१६
१२४/००

क्रमांक:

सेवा-

माननीय मुख्यमंत्री महोदया,
उ०प्र० सरकार, लखनऊ।

विषय:-

विमुक्त जातियों की सूची से त्रुटिवश विलुप्त हुई जातियों को पुनः शामिल
किये जाने सम्बन्धित गुर्जर सद्भावना सभा मुजफ्फरनगर के प्रार्थना पत्र का
अग्रसारण :-

महोदया,

संलग्न गुर्जर सद्भावना सभा के प्रत्यावेदन पर आपने विवेकानुसार अध्यन से मैंने
पाया है कि गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में समाज कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त जातियों
विषयक शासनादेश वर्ष 2001 जारी करते समय शासनादेश 1961 व 1992 का ही संदर्भ लिया गया
व इनके संशोधनो वर्ष 1962 व 1994 का संदर्भ ग्रहण नहीं किया गया। इस चूक से डोम, गुर्जर नट,
बदक, गीधिया, आदि 19 जातियां विमुक्त जातियों की सूची में स्थान पाने से वंचित रह गयीं जो
कि इन जातियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। फलस्वरूप विमुक्त जातियों के अन्तर्गत निलंबने दाली
सुविधाओं से भी ये पूर्णतया वंचित हो गयीं।

आपसे प्रार्थना है कि समाज कल्याण विभाग उ०प्र० नासन द्वारा हुई इस चूक / छूटे
का जल्द सुधार कराकर उपरोक्त 19 जातियों के साथ हुए अन्याय को दूर कराने को कृता
करें।

संलग्न:- गुर्जर सद्भावना सभा मु०नगर
का प्रार्थना पत्र मूल रूप में संलग्नों सहित

भवदीय,

(सूरत सिंह वर्मा)

अध्यक्ष

बहुजन समाज पार्टी
मुजफ्फरनगर